(II) The Reserve Bank of India (Second Amendment) Bill, 1991

SECRETARY-GENERAL: Madam, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Reserve Bank of India (Amendment) Bill, 1991, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 9th January, 1991."

"I am directed to inform you that the Reserve Bank of India (Amendment) Bill, 1990, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 27th December, 1990, has been Passed by Lok Sabha at its sitting held on the 9th January, 1991, with the following amendment:—

Clause 1 Page 1, lines 3 and 4,— *for'** (Amendment) Act, 1990" *substitute* "(Second Amendment) Act, 1991"

2. I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 121 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha with the request that the concurrence of Rajya Sabha in the said amendment be communicated to Lok Sabha.[1]'

Madam, I lay a copy of each of the Bills on the Table.

THE WILD LIFE (PROTECTION) AMENDMENT BOLL, 1991

IHE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS (SHRIMATI MANEKA GANDHI): Madam, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Wild Life (Protection) Act, 1972.

The question was put and the motion was adopted -

SHRIMATI MANEKA GANDHI: Madam, I introduce the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, short-duration discussion on price situation, Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare. *(Interruptions).* Price-rise is more important than anything else.

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): महोदया, पुरलिया में 6 आदमी मारे गये हैं। प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर जी पुरलिया। पश्चिम बंगाल जाने वाले है। अब आतंकवादी पश्चिमी बंगाल के सारे जिलों में घुस गये हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये और प्रधान मंत्री को अपनी यात्रा स्थगित करनी चाहिए...**(व्यवधान)** ।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार): महोदया, मैं हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स कम्पनी के बारे में कहना चाहता हूं...**(व्यवधान)** ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not calling anybody else. I am only calling Mr. Murli Bhandare on the price situation discussion. *(Interruptions).* I am not calling anyone else. I am calling only Mr. Murli Bhandare.

डा० रत्नाकार पाण्डेय: पश्चिम बंगाल में पंजाब के आतंकवादी घुस गये हैं और पुलिस वालों को मार रहे हैं। प्रधानमंत्री 13 तारीख को पुरलिया जाने वाले हैं...**(व्यवधान)** । मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में आतंकवादी घुस गये हैं, सरकार उन पर नियंत्रण करें... **(व्यवधान)** ।

उपसभापति: आपकी बात सुन ली गई है। अब आप बैठिये।

डा० रत्नाकार पाण्डेय: प्रधान मंत्री पुरलिया जाने वाले हैं। वहां पर पुलिस के लोग मारे गये हैं...**(व्यवधान)** ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are other people also in this House.

पाण्डेय जी, पहले ही आपने कह दिया, आपकी बात हो गई। अब तो बैठ जाइये। दूसरे लोग भी हैं हाउस में...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Madam, the Prime Minister of this country...*(Interruption)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let Mr. Hanspal speak. He hardly ever speaks in the House. *(Interruption)*. I will allow. Let me hear him first. At least, let me hear somebody who hardly ever speaks. **हंसपाल जी क्या कह रहे हैं आप? हंसपाल जी को कहने दीजिये...(व्यवधान)**. I will listen to you. Wait for a minute. Please sit down. **(व्यवधान)...मैं महिलाओं की बात सुनूंगी।**

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश): मैडम, आप महिलाओं की बात सुन लीजिये। **(व्यवधान)...**

उपसभापति: महिलाओं की बात भी सुनूंगी। **(व्यवधान)**

body but please sit down. If your do not sit down, nothing will be recorded. Nobody can hear anything. Neither I can hear/anything nor your purpose will be served. Your purpose will be defeated because you would not be able to be understood by anyone. So it is better let me allow one by one. Please sit down.

श्रीमती सत्या बहिन: महोदया, मैं सिर्फ एक संदेश बोलना चाहूंगी।

उपसभापति: नहीं नहीं, आप बैठ जाइये, सत्या बहिन। कृपा करके आप बैठ जाइये। ...**(व्यवधान)**...सुनिये, आप बैठ जाइये। हंसपाल जी आप बोलिये।

I have Identified him. *(Interruptions)*. I will allow everybody. I have identified everyone who is so impatient to speak. *(Interrruptions)*. Yes. I have seen everyone and it is recorded that I have identified everyone who is impatient to speak.

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल (पंजाब): **मैडम, मैं सरकार का ध्यान पंजाब के अंदर परसों रात को एक ही कम्युनिटी के 12 लोग जो मारे गये हैं उसकी** तरफ दिलाना चाहता हूं। इस बात का जो सीरियस डाइमेंशन है वह यह है कि लोग तो वहां 40-40. 50-50 मारे जाते हैं लेकिन जो सीरियस डाइमेंशन है वह यह कि लुधियाना में जहां पर आतंकवाद की घटनायें कम से कम हुई हैं वहां एक गांव के अंदर साढ़े पांच घंटे तक आतंकवादी एक कम्युनिटी के लोगों को उनके घरों से निकालते रहे और निकालकर उनको साढ़े पांच घंटे बाद सड़क पर लेजाकर, उन्हें खेतों में लिटाकर गोली से मार दिया। मैं जानना चाहता हूं कि इन साढ़े पांच घंटों के अंदर पुलिस कहां थी जब कि यह कहा जाता है कि जगह जगह पर नाके लगाये गये हैं और जो लोग वहां पर ट्रैवल करते हैं उनको रोक-रोक कर तंग किया जाता है। तो इन साढ़े पांच घंटों पुलिस कहां थी और क्या कर रही थी? महोदया, परसों प्रधानमंत्री जी सार्क के बारे में जवाब दे रहे थे तो सदस्यों ने पूछा कि इंडो-पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में पाकिस्तान से जो बातचीत हो रही है उसके लिये आपने आतंकवाद के संबंध में क्या कहा, वहां पर जो टैरोरिस्ट कैंप हैं उनके लिये क्या किया और जो वे इन्हें वेपन सप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में क्या किया तो प्रधानमंत्री जी ने इसको लाइटली अवाइड कर दिया, इवेड कर दिया यह बात बहुत अच्छी नहीं है। पंजाब में चीफ सेक्रेटरी को भेजने के लिये पिछले दस दिनों से अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं।

उपसभापति: अगर आपको आइडेंटीफाई किया है तो अपनी बात संक्षेप में बोलिये।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: बस मैं खत्म कर रहा हूं। लेकिन आज तक यह फैसला नहीं हो सका है। इस द्विविधा की हालत के अंदर वहां पर जो घटनायें हो रही हैं वह बढ़ती ही चली जा रही है और ये चीजें पंजाब के उन हिस्सों में भी फैल गई हैं जहां पर आतंकवाद का नाम नहीं था। तो मैं सरकार का इस तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा और ऐसी घटनायें दुबारा न घटें इसके लिये सरकार आवश्यक प्रबंध करे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. R.K. Poddar. I will allow you, Mr. Ahlnwalia. I will allow you to speak on your own, on this subject or on any subject. Just a minute. I have identified Dr. Poddar. Let him speak. Today, I said, those who are hardly ever heard, will be allowed because they have not

[The Deputy Chairman] got the benefit of a loud voice. *(Interruption)*

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): Madam, you are our custodian also.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will allow. But if everbody speaks properly, then I am sure, your purpose will be served better. That is all.

DR. R.K. PODDAR (West Bengal): Madam Deputy Chairman, I want to bring to the notice of the Government a serious matter that has been reported in the *Times of India* on January 9th. Madam, the Director General of the Indian Council of Medical Research, has issued a directive on 12th of December that services of about 20,000 medical and scientific research scholars and technicians are terminated with immediate effect.

Madam, you know the Indian Council of Medical Research is the premier coqr-dinating body that carries on research in medical care, health-related problems. To maintain institutions like the All India Institute of Medical Sciences...*(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to attend a meeting of the Business Advisory Committee. Prof. Chandresh Thakur is going to take the Chair. I have told him to call all those people first who are never heard before and then everybody else. He will allow you one by one, but don't disturb him.

(The Vice-Chairman, Prof. Chandresh P. Thakur in the Chair)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Let him continue. Don't make this seat a hot seat on a cold morning in winter.

DR. R.K. PODDAR: Sir, we are all concerned about the brain drain and other things. These people whose services are being terminated are temporary reasearch fellows and are highly trained medical people in India. They have M.S. and M.D. degrees and they are carrying on research in various fields. The Director-General, Mr. A.S. Paintal, who seems to be...

THE VICE CHAIRMAN [PROF. CHANDRESH P. THAKUR]: Please conclude.

DR. R.K. PODDAR: I am concluding, Sir. We have a Health Minister who is an ex- Vice-Chancellor of two universities. He should personally look into this matter and solve it and have a dialogue with those people whose services are being terminated, (ends)

THE VICE-CHAIRMAN [PROF. CHANDRESH P. THAKUR]: Mrs. Veena Verma... *(Interruptions)*.. .The priority has to go to those who have been getting less chance.

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, यह 10 लाख महिला बैंक कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों के हनन का मामला है। इण्डियन बैंक एसोसियेशन, बैंक प्रबन्धक संगठन, बैंक कर्मचारी संगठन, बैंक इम्पलाइज़ एसोसियेशन, नेशनल फेडरेशन आफ बैंक इम्पलाइज़ ने एक सार्वजनिक मीटिंग की और इन्होंने पांचवें द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत निर्णय लिया है कि महिला बैंक कर्मचारियों को मेटूनिटी लीव से महरूम रखा जाएगा। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि महिला कर्मचारी प्रसूति सुविधा अधिनियम के अन्तर्गत पूरे सेवा काल में 12 महीने मेटूनिटी लीव ले सकती हैं लेकिन इस अधिकार से 10 लाख महिला बैंक कर्मचारियों को मरूहम रखना उनके प्रति अन्याय, गैरकानूनी, असमानता और तानाशाही का रवैया अपनाने का क्या कारण है। महिला संगठनों की भी शिकायत है कि इसके बारे में महिलाओं को न तो वहां बुलाया गया और न ही उनसे मशविरा किया गया बल्कि इस बात को छिपाया गया। यह निर्णय महिला कर्मचारियों के संगठन से पूछे बिना कैसे ले लिया गया। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि सरकार इस पर ऐक्शन ले और कार्यवाही करे कि ऐसा क्यों किया गया बल्कि महिलाओं के हक को दिलवाया जाए।

श्रीमती सईदा खातून (मध्य प्रदेश): मैं भी इसका समर्थन करती हूं।

श्रीमती सत्या बहिन: मैं भी समर्थन करती हूं **(व्यवधान)**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय। एक सवाल आतंकवाद का थोड़ा

अधूरा उठाया गया मैं पूरा उठाना चाहता हूं (व्यवधान) समाचार छपा है कि पंजाब के आतंकवादी बंगाल में घुस गये हैं। समाचार यह है कि पुरुलिया में घुसे उनके मुचलका हुआ और वह निकल कर भाग गये, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन बहुत खतरनाक बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चार वर्ष पहले भी आतंकवादी पकड़े थे सिद्धार्थ शंकर रे और जनरल बरार के मर्डर के इरादे से गये थे।

मुझे लगता है कि उनका इरादा भी किसी खतरनाक काम को करने का है। हम जनरल वैद्य को खो चुके हैं। मैं दो बातें सरकार से निवेदित करना चाहता हूं। पहला, दो बड़े व्यक्तियों, जनरल बरार और सिद्धार्थ शंकर रे की सुरक्षा की पूरी-पूरी व्यवस्था की जाए। दूसरा, ऐसा लगता है कि आतंकवादी देशभर के अंदर घुस रहे हैं, केवल बंगाल, में नहीं। मैं बंगाल की सरकार को दोषी नहीं ठहराना चाहता हूं। लेकिन एक योजना बने जिसमें हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर कार्यवाही की जाए। तीसरा, सरकार की तरफ से जो यह बातचीत का इशारा किया जा रहा है यह इशारा खतरनाक है। टेरोरिस्ट्स से बात नहीं की जानी चाहिए। एक सार्वदेशिक योजना बननी चाहिए।

DEMAND FOR WITHDRAWAL OF GOVERNMENT RECOGNITION TO THE PRESENT INDIAN OLYMPIC ASSOCIATION AND HOLDING OF ELECTIONS TO IT

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, I want to draw the attention of the Government, through you, to a very serious matter about the fate of the Indian Olympic Association where a fight has been going on. Even during V.P. Singh Government Mr. V.C. Shukla illegally took over the presidentship in a meeting where other people were present. I am not goint into details because of lack of time.. Various court proceedings were initiated. The last judgement came on the 3rd January, 1991. A Full Bench judgement of the Madras High Court said that Mr. V.C. Shukla and Mr. Adityan should keep away from the IOA. In direct violation of the court order, the External Affairs Minister of India is still continuing to function as the president of the Indian Olympic Association. He has even issued a statement to the newspapers that he wants to hold elections and that he continues to the president of the IOA. It is a clear case of contempt of court being committed by the Minister of External Affairs. This is not the way the Minister of External Affairs should be functioning. I would request the Government to immediately withdraw the temporary recognition given to the IOA in obedience of the orders of the Madras High Court and ask Mr. Shukla to keep away from the functions of the IOA.

SHRIMATI MARGARET ALVA (Karnataka): I associate myself with what Mrs. Jayanthi Natarajan has said. It is very important to note that the High Court has appointed an Administrator to perform the duties or functions of the president of the IOA—Justice Natarajan has been appointed the Administrator—until elections are held. It is he who should call for elections and not Mr. V.C. Shukla. Mr. Shukla cannot violate the directions of the High Court. Does he think he is a law unto himself because he is an External Affairs Minister?

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Being External Affairs Minister he cannot take the law into his hands and violate the provisions of law. He cannot act as the president...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): The point has been made. You only associate yourself. The Price Rise Discussion, as you all know, is very important. It is an issue which is hanging for long. There is no additional point being made on IOA-You only associate yourself with Mrs. Jayanthi Natarajan.

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. V.C. Shukla had taken 100 persons with him and illegally occupied the office. This is not the way the External Affairs Minister should conduct himself.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): The two